High Powered Commission on Pay Party for Income Tax, Excise and Customs Staff

1731. SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) When the recommendations of the High powered Commission on pay parity for the Income Tax, Customs and Excise department staff placed before the Government for consideration;

(b) What are the recommendations made by the High-powered Commission on pay parity;

(c) Whether it is a fact that the recom mendations are awaiting clearance of the expenditure department as on date *i.e.* 11.11.1998; and

(d) what is the reasons for the abnor mal delay in arriving at the conclusion by the expenditure department?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): (a) No High-powered Commission was set up on pay parity of the Income Tax, Customs and Excise department staff.

(b) to (d) Do not arise in view of (a) above.

Complaints against M/s. Okara Agro Industries Ltd.

1732. SHRI A. VIJAYA RAGHAVAN: Will the Minister of FINANCE be pleased to State:

(a) whether Government have received reprsentations/complaints from a large number of investors/depositors against M/s. Okara Agro Industries Limited, New Delhi regarding irregularities, As-toppage of maturity value of their depo-site since March, 1998;

(b) if so, what action Government have taken to regulate, control and stop the misuse of investors' money to the extent of nearly rupees three crores collected from nearly 35000 depositors by this company; and

(c) what action Government have taken to regulate, control and stop the misuse of investors' money?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

ऋण वसूली प्राधिकरणों में दर्ज किये गये मामले

1733. **श्री ओंकार सिंह लखावत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 1998 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों की बैक-वार अनुपयोज्य आस्तियां कितनी हैं और बैंकों के कुल ऋण में उनकी प्रतिशतता कितनी हैं; और

(ख) सरकार द्वारा बड़े ऋणों की वसूली के लिए बनाये गये ऋण वसूली प्राधिकरण में कितने मामले दर्ज किए गए हैं और उनकी राशिंया क्या हैं, इनमें से कितने मामलों का फैसला हुआ तथा इनके माध्यम से अब तक कितनी राशि वसूली की गई हैं?

वित्त मंत्रालय (बैकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर जनार्दनन) : (क) दिनांक 31 मार्च, 1998 की स्थिति के अनुसार धनराशि एवं प्रतिशत की दृष्टि से राष्ट्रीयकृत बैंकों की बैंक-वार अनुपोज्य आस्तियां सलंग्र विवरण में दर्शाई गई हैं (नीचे देखिए)

(ख) दिनांक 31 मार्च, 1998 की स्थिति के अनुसार ऋण वसूली अधिकरण डीआरटी को अन्तरिक/दायर किए गये 16107 मामलों में से डीआरटी द्वारा 1157.96 करोड़ रूपए के 2271 मामलों पर निर्णय ले लिये गये हैं औश्र 13836 मामले उनके पास लाम्बित है। 246.19 करोड़ रूपए की राशि वसूल कर ली गई हैं।

विवरण

मूल्य के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों की सकल और निवल अनिस्पादित आस्तियां और 31.3.98 **की स्थिति के अनुसार सकल/निवल अग्रिमों का प्रतिशत**

(**राशि करोड़ रूपये**)

बैंक का नाम	**सकल राशि**	**अनिस्पादित आस्ति**	**निवल राशि**	**अनिस्पा. आस्ति निवल अ.का%**
इलाहाबाद बैंक	1458.93	23.18	859.86	15.09%
आन्ध्रा बैंक	341.30	9.86	93.76	2.92
बैक आफ बडौदा	3129.28	14.63	1290.35	6.60
बैक आफ इंडिया	2669.00	11.55	1570.00	7.13
बैक आफ महाराष्ट्र	709.09	17.39	316.57	8.59
केनरा बैक	3580.81	18.69	1255.29	7.52
सेंट्रल बैक आफ इंडिया	2414.53	20.47	1384.74	12.21
कापोर्रिशन बैंक	341.86	7.60	125.46	2.93
देना बैंक	774.79	13.73	439.43	8.28
इंडियन बैंक	3428.39	38.96	1886.67	26.01
इंडियन ओवरसीज बैंक	1255.00	13.38	543.00	6.26
ओरियंटल बैंक	397.23	6.16	287.15	4.84
पंजाब एंड सिंध बैंक	1038.90	26.79	345.08	10.84
पंजाब नेशनल बैंक	2447.00	14.50	1526.00	9.60
सिंडिकेट बैंक	1185.29	15.31	401.94	5.78
यूको बैंक	1780.30	24.04	705.12	11.14
यूनिय बैक आफ इंडिया	1194.73	11.18	787.89	7.66
यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	1451.00	33.50	415.00	12.10
विजया बैंक	532.95	15.21	276.16	7.50
राष्ट्रीयकृत बैंकों का योग	30130.38	16.88	14440.50	8.87

Funding of Development Activities by Insurance Companies

1734. SHRI NILOTPAL BASU: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government has decided to allow private companies to operate in the insurance sector;

(b) whether it is also a fact that Government is also allowing foreign equity participation in such private operations;

(c) if so, the impact on investable resources and tax made available to Government by the LIC and GIC in the last three years for addressing the social, development and infrastructural needs;